

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 05 मार्च, 2009

विषय:-जनपद नैनीताल के तहसील धारी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-288/18(1)/2007 दिनांक 14.03.2008 एवं शासनादेश संख्या-288(1)/18(1)/2007 दिनांक 20.03.2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य हेतु औचित्यपूर्ण गयी लागत रु0 160.80 लाख के सापेक्ष अब तक अवमुक्त कुल धनराशि रु0 90.00 लाख के उपयोग कर लिये जाने के फलस्वरूप अब तक अवमुक्त धनराशि को कम करते हुये चालू वित्तीय वर्ष में अवशेष धनराशि रु0 70.80 लाख (रु0 सत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. कार्य करने से पूर्व मदवार विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
2. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्य निधारित समय पर पूर्ण करा लिया जाय। योजना का पुनरीक्षण आगणन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए ही पूर्ण की जाय एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाय।
5. निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय।
6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया

जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-6 लेखाशीर्षक-4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-03-तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-674 NP/XXVII(5)/2008 दिनांक 19.2.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या-298(1)/XVIII(1)/2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
6. अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग-5
11. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।